consumer products. Now we want to launch upon the export of capital goods.

बिहार में छोटे पैमाने के उद्योग

*७७१. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में भारत सरकार ने बिहार सरकार को छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए २० लाख रुपये का आवंटन किया था ;

(ख) क्या उक्त रकम पूर्णत : खर्च कर दी गई थी ; और

(ग) १९६२ से १९६५ की अवधि में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को कितनी रकम दिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). मांगी गई जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) भारत सरकार ने १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए बिहार सरकार को अस्थायी रूप से ६०.७५ लाख रुपये (२४.८२ लाख रु० अनुदान तथा ३५.९३ लाख रूपये ऋण के रूप में) की राशि मंजूर की थी ।

(ख) बिहार की सरकार ने बताया है कि वर्ष १९६१-६२ में छोटे पैमाने के उद्योगों पर लगभग ५३.०८ लाख रु० खर्च हुआ ।

(ग) राज्य सरकारों को छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए वार्षिक आधार पर राशि आवंटित की जाती है । ये आवंटन राज्यों के वार्षिक कार्यक्रम, उन्हें पिछले वर्ष दी गई सहायता, कुल पूंजी व्यय, केन्द्र के पास उपलब्ध साधन, राज्य सरकारों ने पहले कैसा काम किया आदि विभिन्न बातों को ध्यान में रख कर किये जाते हैं । इस समय यह बता सकना संभव नहीं है कि १९६२-६३ से १९६५-६६ की अवधि में बिहार की सरकार के लिए कितनी रकम आवंटित की जाएगी ।

[(a) to (c). A statement giving the information asked for is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) During the financial year 1961-62, the Government of India had provisionally sanctioned a sum of Rs. 60·75 lakhs (Rs. 24·82 lakhs as grants and Rs. 35·93 lakhs as loans) to Bihar Government for the development of Small Scale Industries.

(b) The Bihar Government have reported an expenditure of about Rs. 53·08 lakhs for Small Scale Industries during the year 1961-62.

(c) Allocations to State Governments for Small Scale Industries are made on an annual basis, taking into account various factors, namely, State's Annual Programme, assistance provided during the previous year, total Plan outlay, resources at the Centre, past performance of the State Governments, etc. It is not possible to say at this stage what amounts will be allocated to Bihar for the years 1962-63 to 1965-66).]

श्री योगेन्द्र झा : आगे के लिए जो एलाटमेंट बिहार सरकार को किया गया है लघु उद्योगों के लिए, क्या उसके लिए बिहार सरकार ने पहले से कोई योजना बना ली है और इसकी जानकारी भारत सरकार को है ?

श्री कानूनगो : अभी तो जो काम चल रहा है वह १९६१-६२ का काम चल रहा

है । आपने १९६५-६६ की जो चीज है और इसके पहले की जो चीज है, उसके बारे में पूछा है । इसका जवाब यह है कि हर साल प्लानिंग कमिशन और मिनस्ट्री आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की आपस में डिसकशन होती है और उसमें जो प्लान निकलता है, उसी के आधार पर एलोकेशन होता है ।

श्री योगेन्द्र झा : मैंने यह नहीं पूछा था । मैंने पूछा था कि.....

अध्यक्ष महोदय : आपने यह पूछा था कि जो आप ग्रांट देने वाले हैं उसके लिए बिहार गवर्नमैंट ने कोई प्लान बना लिया है और सैंट्रल गवर्नमैंट को इत्तला दे दी है । उन्होंने जवाब दिया है कि हर साल जब वह बनता है कि तो उस गवर्नमैंट के नुमाइंदे यहां पर प्लानिंग कमिशन से सलाह करके उसको तैयार करते हैं ।

Shri Vishram Prasad: May I know from the hon. Minister whether any similar scheme is also there for the eastern districts of U.P. for removing the poverty there?

Mr. Speaker: That is not relevant here.

Shri Bhagwat Jha Azad: May I know if any assessment has been made as to how for this expenditure of Rs. 53 lakhs is commensurate with the production in this field?

Shri Kanungo: Yes, Sir. The production figures are obtained from the State Government and the production figures are going up. To relate a particular investment in the particular year is not easy. The cumulative effect of past investments and past operations has got to be taken into account. Therefore it will not be correct to relate any investment relating to any production.

श्री विभूति मिश्र : जितनी रकम बिहार सरकार को स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए दी जाती है, उसके बावजद भी प्रधान मंत्री जी ने बराबर यह कहा है कि बिहार में बहुत ज्यादा गरीबी है । क्या सरकार यह सोचती है कि इस एमाउंट को बढ़ाया जाए ?

Shri Kanungo: Commensurate with the availability of resources the effort always is to provide for the amount which can be effectively spent by the State Governments. These matters are discussed by the Planning Commission.

Dandakaranya

***772. Shrimati Renu Chakravartty:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than 650 refugees who went to Manipur and have to date received neither homestead plot, nor cultivable land, have applied to go to Dandakaranya;

(b) whether it is a fact that they have been refused to be taken to Dandakaranya;

(c) if so, why; and

(d) what alternative rehabilitation they can get?

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Mehr Chand Khanna): (a) to (d). These are unsponsored displaced persons most of whom had migrated to Manipur many years ago. They have been carrying on their livelihood so long without any aid from Government and could not be considered for rehabilitation benefits after the lapse of all these years.

Shrimati Renu Chakravartty: Is it not a fact that these refugees have been applying for benefits long before the closure of the department in Manipur itself and even at the time of the closure they had made many requests to Government? Why are they now being excluded from being considered as refugees who are within the residuary problem?

Shri Mehr Chand Khanna: The total number of refuges who came to Manipur is roundabout 2,000. I have been